ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

भारत में खाद्य सुरक्षा एवं चुनौतियाँ

डॉ. प्रवीण कुमार
पूर्व शोध–छात्र, वाणिज्य विभाग
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (बिहार)

सार

खाद्य सुरक्षा एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुंच है। भारत वास्तव में अब विकसित हो रहा है और इसकी आय, बुनियादी ढांचा, प्रति व्यक्ति आय भी विकसित हुई है। लेकिन भारत के सामने प्रमुख समस्या है 'खाद्य प्रबंधन और इसका वितरण'। कृषि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी जनसंख्या का 55 प्रतिषत रोजगार और अपनी वार्षिक जीडीपी का 16.5 प्रतिशत प्रदान करता है। आज, भारत दुनिया भर में कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत दूध, काजू, नारियल, चाय, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी आबादी (281 मिलियन) है। यह गेहूं, चावल, चीनी, मूंगफली और अंतर्देशीय मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह तंबाकू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केले के उत्पादन में भारत प्रथम श्रेणी के साथ विश्व फल उत्पादन का 10 प्रतिषत है। भोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिशचित करने के बावजूद, देश में सूक्ष्म स्तर पर खाद्य असुरक्षा का अस्तित्व भारत के लिए एक कठिन चुनौती बना हुआ है। 2013 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत 120 देशों में से 63 वें स्थान पर है और यह रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है क्योंकि भारत दुनिया में भोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। फिर भी भारत लोगों की बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। भारत में बहुत से लोग हैं जो वर्ग भोजन के लिए भी कड़ी मेहनत करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गाँव के क्षेत्रों में लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख शहरों में भी लोगों को समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति की कमी और पोषण की कमी न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि के लिए एक बुरा निशान है, बल्कि यह देश की विकासशील आर्थिक नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खाद्य उत्पादों का कुप्रबंधन और इसकी आपूर्ति देश को कई भयानक बीमारियों से भी बचाती है! यह पत्र भारतीय परिदृश्य में प्रचलित कई खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य–शब्द: *खाद्य सुरक्षा; चुनौतियां; उपाय; मुद्दे; सिफारिश।*

परिचय

हवा और पानी की तरह जीने के लिए खाना जरूरी है। यह दो वर्ग भोजन प्राप्त करने से अधिक है। इसके तीन आयाम हैं– 1) खाद्य उपलब्धता यानी देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन और सरकार में अनुरक्षित खाद्य प्लस ऑयलर स्टॉक। 2) फूड एक्सेसिबिलिटी यानी भोजन हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर होना चाहिए। 3) खाद्य सामर्थ्य यानी किसी व्यक्ति के पास अपनी आहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के भारी दबाव के कारण हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भारत ने न केवल विकास और प्रगति देखी है, बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। यह उपलब्धि उस समय एक विकट मोड़ ले लेती है जब कोई अपने भीतर पनप रही भूख की समस्या को

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

देखता है। 1.27 बिलियन आबादी के अनुमान के अनुसार, कुल 77 प्रतिषत गरीब और कमजोर माने जाते हैं, और लाखों लोग एक दिन में दो समय भोजन प्राप्त करने में विफल होते हैं। 2013 के हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत 120 देशों में से 63 वें स्थान पर है और यह रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है क्योंकि भारत दुनिया में भोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इस समस्या का अस्तित्व केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बलकि शहरी क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। इस बारहमासी समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने कुछ प्रमुख कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना आदि की शुरुआत की। यह प्रमुख कार्यक्रम समाज के हर वर्ग में प्रवेश करने में विफल है और गरीब लोगों के बीच भूख जारी है। इस कार्यक्रम की विफलता में निराशा को मुख्य रूप से समाज के बीच असमानता की व्यापकता, सार्वजनिक सेवाओं की असफल डिलीवरी, दयनीय देयता प्रणाली और गरीब समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन में उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने 2010 में एक नए खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किसी भी सरकार के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाले भोजन के वितरण के लिए दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है। । बहुत बहस और विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया और 12 सितंबर 2013 को एक कानून बन गया। इस अधिनियम के अनुसार, खाद्य सुरक्षा को घरेलू मांग के साथ–साथ व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। सस्ती कीमतों पर भोजन के पर्याप्त साधनों के लिए खाद्य सुरक्षा की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त परिभाषा अपने सभी सदस्यों के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन सुनिशचित करने के लिए हर समय घरेलू स्तर पर भोजन उपलब्ध होता है। गृहस्थी को विचार के लिए इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसके बजाय, हम कहते हैं, एक देश या उसके एक प्रशासनिक सबयूनिट क्योंकि खाद्य सुरक्षा सार्थक होने के लिए, भोजन न केवल इन उच्च स्तरों पर उपलब्ध होना चाहिए, बल्कि सुलभ होना चाहिए सबसे कम इकाई, घर और वास्तव में इसके भीतर भी हर एक सदस्य को उपलब्ध होना चाहिए। वास्तव में, खाद्य सुरक्षा का एक केंद्रीय पहलू उपलब्धता (उच्च स्तर पर) और पहुंच (न्यूनतम स्तर पर) के बीच विसंगति है। स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन से बढ़ कर हाल के वर्षों में 200 मिलियन टन से अधिक हो गया। हालाँकि आजादी के समय जो उत्पादन हो रहा था और उसके बाद के कुछ दशकों में लोगों की कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, हम अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ अगर उत्पादन किया जाता है तो सभी को समान रूप से वितरित किया जाता है, सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं आधी से अधिक सदी में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि के बावजूद मुलाकात की जा सकती है।

भारत की खाद्य सुरक्षा चुनौतियां

खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा को भोजन की उपलब्धता और उस तक पहुंच के रूप में परिभाषीत किया जा सकता है। एक परिवार को तब भोजन सुरक्षित माना जाता है जब उसके सदस्य भुखमरी में नहीं रहते हैं या भुखमरी के डर से नहीं रहते हैं। एफएओ की परिभाषा के अनुसार– खाद्य सुरक्षा मौजूद है, जब सभी लोग, हर समय, एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार आवश्यकताओं और खाद्य वरीयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक पहुंच रखते हैं। भोजन की खपत के स्तर और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। भारत में 1990 के दशक के मध्य से 30 मिलियन लोगों को भूखे रहने की श्रेणी में जोड़ा गया है और 40ः बच्चे कम वजन के हैं। विश्व में 852 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी के कारण भूखे हैं और 2

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

बिलियन लोगों में गरीबी की बदलती डिग्री के कारण खाद्य सुरक्षा की कमी है (स्रोत एफएओ, 2003)। 600 मिलियन बच्चे हर साल और 17000 हर रोज भूख से मरते हैं। भारत में लगभग 320 भारतीय हर रात बिना भोजन किए बिस्तर पर चले जाते हैं और हाल ही में डेटा बहुत अधिक चिंताजनक है और स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। दुनिया के कई देशों में खाद्य दंगे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ग्रामीण संदर्भ में, छोटे और सीमांत किसान के लिए कृषि विकास खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। भोजन के लिए कृषि का विविधीकरण, अनाज, दालें, खाद्य तेल उपज, सब्जी, ईंधन और, लकड़ी उपज वाले पौधे, औषधीय और चारे की फसलें खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और किसानों को आय बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। अत्यधिक वर्षा, सूखा, और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, उदीयमान स्थलाकृति, मृदा अपरदन और मृदा प्रकार जैसे अपमानित मिट्टी, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी जैसी प्राकृतिक योनियाँ खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। किसान परिवारों का आय स्तर खाद्य सामर्थ्य तक पहुँच को नियंत्रित करता है। खाद्य वितरण एक बड़ी समस्या है। पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। पर्याप्त आय के भीतर बहुत गरीब परिवार खाद्य संकट से बच नहीं सकते हैं। वैश्वीकरण खाद्य सुरक्षा में मदद कर सकता है और नहीं भी। हालांकि, ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वैश्वीकरण निश्चित रूप से व्यापार के कारण खाद्य सुरक्षा में मदद करेगा लेकिन यह बहस का विषय है। हमें विकासशील और स्थिर खाद्य उत्पादन के माध्यम से विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रौद्योगिकियों एवं विधियों पर बनाना होगा। कृषि में विविधता की अत्यधिक आवश्यकता है। हम कुपोषण और अकाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तदनुसार, हम सभी सहित सरकार। वर्तमान मांग को पूरा करने और देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की खाई को भरने के लिए नीतियों को गंभीरता से नया स्वरूप देने की आवश्यकता है।

संदूषण की चुनौती

• फिर भी, खाद्य सुरक्षा, जो भुखमरी को समाप्त करना चाहती है, खाद्य अपमिश्रण को समाप्त नहीं करती है। वस्तुतः भारत में भोजन की सभी वस्तुओं में रसायन या मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो उन्हें विभिन्नि डिग्री के लिए असुरक्षित बनाते हैं। इसलिए, प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान, जहाँ भोजन परोसा जाता है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ परोसा जाता है वह रासायनिक रूप से सुरक्षित हो, पोषण से स्वस्थ हो और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए बना हो।

• इसका मतलब सार्वजनिक स्थानों पर दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता के निरीक्षण की एक संगठित प्रणाली है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यहां तक कि गोदामों में भी जहां अनाज को आसान वितरण के लिए रखा गया है, उसमें पर्याप्त सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

• भोजन बनाने का व्यवसाय आकर्षक और आकर्षक दिखाई देता है, जो हम खाते हैं, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए, प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन खरीदने में सक्षम होना चाहिए जो संदूषण से मुक्त हो। इसमें गांवों में भी परीक्षण सुविधाओं या प्रयोगशालाओं से संबंधित एक व्यापक प्रक्रिया शामिल होगी। हमारे पास एक खाद्य सुरक्षा परियोजना होनी चाहिए जो कि हम पौषटिक खाएं। प्रत्येक परिवार को निश्चित मात्रा में अनाज के प्रावधान से खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है लेकिन यह सुनिश्चित करके कि वितरित किया गया हर अनाज पौष्टिक और पौष्टिक है, न कि हानिकारक। खाद्य सुरक्षा की विचारधारा एक समग्र है, केवल शारीरिक रूप से अनाज उपलब्ध कराने से परे है।

उपाय की जरूरत है

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

• हमारे पास एक राज्य–प्रायोजित खाद्य सुरक्षा नींव होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक राज्य में सभी शाखाएँ हों, उपकरण के साथ जो खाद्य सुरक्षा का परीक्षण कर सकें। प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा कर्मियों का एक सशक्त बल भोजनालयों, खाद्य भंडार, यहाँ तक कि त्यौहार स्थलों पर जाना चाहिए जहाँ भोजन परोसा जाता है, और जहाँ वैज्ञानिक तरीकों से मिलावट या संदूषण का पता चलता है, वहाँ कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा पुलिस के पास विधायी मंजूरी के तहत उपयुक्त शक्तियां होनी चाहिए। एक ऐसा अधिनियम होना चाहिए जो लोगों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक साधन प्रदान करता है। जब्ती की शक्तियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सुरक्षा पुलिस बल एक नई अवधारणा है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करना राज्य का एक मौलिक दायित्व है।

• भारत का भाग्य अभी तक अनिश्चित है। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रतिष्ठित भाषण में कहा "भारत की सेवा का अर्थ उन लाखों लोगों की सेवा है जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञानता और बीमारी और अवसर की असमानता का अंत। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है। वह हमसे परे हो सकता है लेकिन जब तक आँसू और पीड़ाएँ हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। "

• खाद्य सुरक्षा विधेयक में एक गंभीर कमी है, और इसे उपयुक्त संशोधनों और नीति सुधार के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए। सब्जियों और खाद्य पदार्थों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है।

• भुखमरी को समाप्त करने के लिए, सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को विनियमित किया जाना चाहिए। वास्तविक खाद्य सुरक्षा में मानवता के संतोष का साधन नहीं है।

भारत में मुद्दों का सामना

अधिशेष खाद्यान्न भंडार के बावजूद, यह भी एक वास्तविकता है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास दिन में दो बार खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

1. अनाज के लिए अपर्याप्त और अनुचित भंडारण सुविधाएं, जो अक्सर बाहर टार्प्स के नीचे जमा होती हैं जो नमी और कीटों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती हैं।

2. अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन परिवहन प्रणाली फलों, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले उत्पादों को सड़ने का एक प्रमुख कारण है।

3. खराब सड़कें और अक्षम परिवहन प्रणाली बड़े पैमाने पर देरी का कारण बन सकती हैं। यह बदले में तापमान संवेदनशील उपज के क्षय का कारण बनता है।

4. मंडियों की सीमित पहुंच, जो वर्तमान में कृषि उपज के लिए एकत्रीकरण का बिंदु है। इससे छोटे किसानों को परेशानी होती है, जिनके पास अपने निपटान में उचित परिवहन सुविधा नहीं है और उन्हें निकटतम मंडी तक 12 किमी की यात्रा और औसत करना पड़ता है।

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

5. किसान और अंतिम उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की कई परतें, कीमतों में वृद्धि और किसानों के लिए सौदेबाजी की शक्ति और मूल्य पारदर्शिता को कम करना। इन मध्यस्थों ने 250 प्रतिशत (उत्पादन की लागत से अधिक) की मुद्रास्फीति को जन्म दिया है।

6. एक अच्छी तरह से विकसित कृषि बैंकिंग क्षेत्र की कमी, जो किसानों को कमीशन एजेंटों से उच्च ब्याज के साथ ऋण लेने के लिए मजबूर करती है।

7. नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और कृषि उत्पादों पर शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव।

8. खाद्य फसलों की खेती से लेकर फलों, सब्जियों, तेल के बीजों की खेती और धीरे–धीरे औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम करने वाली फसलों के लिए एक क्रमिक बदलाव आया है। इससे अनाज, बाजरा और दालों के तहत शुद्ध बुवाई क्षेत्र में कमी आई थी।

9. कारखानों, वेयर–हाउसों और आश्रयों के निर्माण के लिए अधिक से अधिक भूमि के उपयोग ने खेती के तहत भूमि को कम कर दिया है और अब खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध नहीं है।

10. भूमि की उत्पादकता में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। उर्वरक और कीटनाशक, जो कभी नाटकीय परिणाम दिखाते थे, अब उन्हें मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है

अनुशंसाएँ

मौजूदा महंगे, अक्षम और भ्रष्टाचार से संस्थागत व्यवस्था से उन लोगों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जो पारदर्शी तरीके से अपेक्षित गुणवत्ता वाले अनाज के सस्ते वितरण को सुनिश्चित करेंगे और स्वयं–लक्ष्य हैं।

वायदा बाजार और मुक्त व्यापारः इनपुट सब्सिडी और उच्च एमएसपी द्वारा चिन्हित वर्तमान प्रणाली को चरणबद्ध किया जाना चाहिए। कीमतों में व्यापक उतार–चढ़ाव से बचने और छोटे किसानों द्वारा बिक्री को रोकने के लिए, वायदा बाजार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बेहतर संचार प्रणाली से किसानों को अपनी उपज का बेहतर सौदा मिल सकता है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा योजनाओं को बीमा प्रीमियम के एक प्रमुख हिस्से के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। शुरू करने के लिए, अंतर–राज्य आंदोलन, स्टॉकिंग, निर्यात और संस्थागत ऋण और व्यापार वित्तपोषण के बारे में खाद्यान्नों पर सभी प्रतिबंधों को त्याग दिया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार, उत्पादन और उपभोग की जरूरतों के बीच अंतर को कम करने, आपूर्ति परिवर्तनशीलता को कम करने, संसाधन–उपयोग में दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रों के लिए परमिट उत्पादन में मदद करेगा।

खाद्य–शिक्षा कार्यक्रमः शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए, खाद्य सुरक्षा की जरूरत को स्कूलों में बढ़े हुए नामांकन से उत्पादकता से जोड़ा जा सकता है। पीडीएस से बाहर चरणबद्ध के साथ, गरीब लोगों को उनके हक के आधार पर भोजन कूपन जारी किए जा सकते हैं।

संशोधित भोजन के लिए कार्य योजना– प्रत्यक्ष सबसिडीः इनपुट सबसिडी और एमएसपी के युक्तिकरण के साथ, केंद्र सरकार को पर्याप्त धनराशि दी जाएगी, जो गरीबों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-7 No. 3 July 2020

सामुदायिक अनाज भंडारण बैंक: एफसीआई को धीरे–धीरे नष्ट किया जा सकता है और जिले के प्रत्येक ब्लॉक, गांव में खाद्यान्न बैंकों के निर्माण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत किया जा सकता है, जहां से लोगों को खाद्य कूपन के खिलाफ सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिल सकते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए भोजन के कूपन क्रमिक रूप से गिने जा सकते हैं। मौजूदा ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत अनाज भंडारण की सुविधा दो साल के भीतर बनाई जा सकती है और अनाज के शुरुआती हिस्से मौजूदा एफसीआई शेयरों से आ सकते हैं। यदि सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, तो अपेक्षाकृत सस्ते मोटे अनाज, जैसे बाजरा और रागी और पोषक अनाज जैसे बाजरा और दालें लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाना: सरकार, महत्वपूर्ण कृषी अवसंरचना में निवेश, क्रेडिट लिंकेज और नवीनतम तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के माध्यम से, खाद्यान्न उत्पादन में स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले, ब्लॉक को प्रेरित करती है। हालांकि, केवल चावल या गेहूं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, क्षेत्र में एक संभावित के साथ खाद्य फसल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं की तरह बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कृषि में निजी निवेश का अनुकरण करेगा। स्थायी आधार पर त्वरित खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने और अनाज में मुक्त व्यापार से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इससे तेजी से आर्थिक विकास होगा और लोगों को क्रय शक्ति मिलेगी। इन पर अमल करते हुए पांच साल की ट्रांजिटरी अवधि की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, भारत वास्तविक अर्थों में और वास्तविक समय सीमा में खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन, एकीकृत जल प्रबंधन, कृषि मूल्य निर्धारण, अपर्याप्त भंडारण क्षमता, सार्वजनिक सेवाओं की असफल डिलीवरी, खाद्य उत्पादों के कुप्रबंधन और फसल बीमा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देकर प्राप्त की जा सकती है। उत्पादन में सुधार के लिए काफी प्रयास किए जाने के बावजूद, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के नुकसान को रोकने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। 1.2 बिलियन से अधिक लोगों को खाना खिलाने के लिए, खाद्य अपव्यय के मुद्दे को संबोधित करते हुए भूख से मुकाबला करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के भारत के प्रयासों के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के बावजूद, देश में सूक्ष्म स्तर पर खाद्य असुरक्षा का असतित्व भारत के लिए एक विकट चुनौती बना हुआ है।

संदर्भ

- आईएफपीआरआई, और कंसर्न वर्ल्डवाइड, 2013 ग्लोबल हंगर इंडेक्स – भूख की चुनौतीः बिलडिंग रिसिलिंस टू अचीव फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी। बॉन, वाशिगिटन डी0 सी0, डबलिन, अक्टूबर 2013।
- घोष, एस. और ब्रह्मानंद, पी.एस., जल और खाद्य सुरक्षा, कुरुक्षेत्र, 2009, 57, 1920।
- एफसीआई की रिपोर्ट।
- भारत का सार्वजनिक वितरण विभाग, इंटरनेट।
- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट।
- जयराम, रमेश द इकोनॉमिक टाइम्स, एसईजेड, 10 जुलाई 2012

Copyright © 2020 Authors